कोरोना वायरस महामारी का संदेश

1. **एक घातक जैव-जलवायु संकट हमारे ग्रह पृथ्वी पर मँडरा रहा है**

2. मानव एवं मानव समाज प्रकृति-मानव केंद्रित कार्यक्रम (एजेंडे) से अपने आपको एवं अपनी सामाजिक विश्व व्यवस्था को बदल डाले

उपरोक्त मूल्याँकन की सबसे पहली माँग यह है कि मनुष्य अपनी जैव-सामाजिक (Bio-Social) चरित्र की वास्तविकता (Reality) को ठीक-ठीक पहचान कर ले। प्रत्येक मनुष्य की (अन्य जीवों की तरह) जैविक आवश्यकताएँ जहाँ निजी हैं; वहीं सामाजिक आवश्यकताएँ साझी हैं, एकीकृत हैं। मनुष्य की इस दोहरी-एकीकृत प्रकृति ने इतिहास की वर्तमान मंजिल में हमारे ग्रह के जैव-जीवन में मनुष्य को आभासी तौर पर अन्य जैव-विविधता से ताकतवर बना दिया है। परिणाम स्वरुप एक तरफ मनुष्य जैव-जीवन पर नियंत्रण कायम करने के रास्ते पर भटक गया है; तो दूसरी तरफ ताकतवर मनुष्य कमजोर मनुष्य पर एवं ताकतवर ग्रुप (समुदाय, देश इत्यादि) कमजोर ग्रुप पर कार्पोरेट समाजशास्त्र के माध्यम से नियंत्रण कर रहा है। तथाकथित कानून के राज्य के नाम पर एक दूसरे की सहायता के कानून को भूलता जा रहा है। प्रकृति एवं मनुष्य की आपसी पूरकता के पहलू के बजाय, गैर-पूरकता का पक्षधर बन गया है तथा अपने ही अस्तित्व पर खतरा पैदा कर लिया है।

इस मूल्याँकन की दूसरी माँग यह है कि मनुष्य इस ब्रह्मांड के बहुत छोटे से ग्रह पृथ्वी पर एक जीव है, जो ब्रह्माण्ड के अनंत समय और स्थान में पैदा हुआ है, जो अपने विशिष्ट अस्तित्व, गति और परिवर्तन के नियम के साथ प्रकृति का एक बहुत छोटा भाग है। सम्पूर्ण प्रकृति का अति-सूक्ष्म अंश है। प्रकृति में प्रत्येक कण अपने विशिष्ट गुण के साथ समस्त प्रकृति से अंतर-संबंधित है, अंतर-निर्भर है, अंतर-क्रिया करता रहता है। ऐसा ही मानव जाति अपने विशिष्ट गुण के साथ प्रकृति से सम्बंध रखती है। यह अपने आपको सबसे बुद्धिमान, श्रेष्ठ होने के भ्रम से मुक्ति पाये ताकि प्रकृति से अपनी गैर-पूरकता को बढ़ावा देने की बजाय पूरकता का कदम रख सके और इस धरती के जैव-परिवार के साथ-साथ अपना अस्तित्व बचाए रख सके।

इस मूल्याँकन की तीसरी माँग है कि मानव समाज पैसे (धन) को बड़ी वस्तु (पूँजी) समझने की बजाय प्राकृतिक संसाधनों तथा पर्यावरण एवं मानवता को पूँजी (बड़ी चीज) का दर्जा दे।

इस मूल्याँकन की चौथी माँग यह है कि बाजारवाद की बजाय मानवता, सामाजिक और पर्यावरण सुरक्षा का प्रबंध करे।

इस मूल्याँकन की पाँचवीं माँग यह है कि प्रत्येक मानव की समझ एवं भागीदारी सम्पूर्ण विश्व एवं व्यवस्था के स्तर पर बढ़े। आम जनता के सशक्तिकरण तथा विश्व व्यवस्था के लोकतांत्रिकरण से ही वर्तमान पूँजी आधारित कार्पोरेट समाज की बजाय प्रकृति-मानव समर्थक समाज बनाने की समझ विकसित की जा सकती है।

उपरोक्त दिशा में आगे बढ़ने के लिए:-

1. हमें विश्व समाज में प्राकृतिक कृषि को प्रथम स्थान पर रखने एवं औद्योगिक प्रबंध को गौण करने का कदम उठाना पड़ेगा।
2. हमारे ग्रह को शस्त्र-विहीन एवं सीमा-विहीन बनाना होगा। एकीकृत विश्व-सभ्यता को मजबूत करना होगा।
3. विश्व के प्रत्येक भाग की जलवायु व मिट्टी तथा जैव-विविधता के मुताबिक प्राकृतिक-संसाधनों एवं मानवीय समाज को गठित करते हुए विश्व-व्यापी तौर पर सहयोगी व्यवस्था खड़ी करनी होगी।
4. हमारे वैज्ञानिक-तकनीकी ज्ञान का सदुपयोग जैव-विविधता को बचाते हुए सम्पूर्ण मानवीय समाज की पर्यावरण और सामाजिक सुरक्षा को सुनिश्चित करना होगा।
5. पुनः अब मानव समाज को पर्यावरण-लोक नेतृत्व आधारित लोकतांत्रिक समाज की रचना करना हमारे अस्तित्व की पहली शर्त है। लोकतांत्रिक उसूल व्यक्ति, परिवार, देश और दुनिया (यानि प्रत्येक स्तर पर) के स्तर पर लागू करते हुए आम जनता को निर्णय लेने के अधिकारों में शामिल करके प्रत्येक इकाई के सम्बंधित लोगों की समझदारी, भागीदारी एवं सशक्तिकरण हर स्तर पर सुनिश्चित किया जाए।

इस रणनीतिक दिशा (प्रकृति-मानव केंद्रित एजेंडे वाली दिशा) के साथ ही वर्तमान कोरोना महामारी से निपटने के लिए प्रत्येक व्यक्ति, परिवार से लेकर विश्व समाज की सामाजिक एकता

(Social Solidarity) को जितना सम्भव हो, मजबूत किया जाए। इसमें एक तरफ प्रत्येक व्यक्ति का योगदान, भागीदारी जरुरी है, तो दूसरी तरफ निर्णयकारी ताकतें (विश्व की सरकारें, राजनीतिक पार्टियाँ, कार्पोरेट घराने, मीडिया, सिविल सोसायटी, प्रशासन, डॉक्टर इत्यादि) लोगों को सूचित करते हुए तथा उनके सहयोग और भागीदारी को सुनिश्चित करके महामारी के मुकाबले के लिए अपने संसाधन और योजना की सम्पूर्ण ताकत के साथ आगे आयें।

कोरोना वायरस महामारी हमारे लिए जहाँ अस्तित्व की चुनौती पेश कर रही है, वहीं हमारी समझ को दुरुस्त करने का अवसर प्रदान कर रही है। यह चुनौती एवं अवसर दोनों है।

सार-संक्षेप

सार-संक्षेप में प्रकृति-मानव केंद्रित कार्यक्रम न केवल पर्यावरण एवं मानव संसाधनों के कार्पोरेट कुप्रबंध द्वारा पैदा की गयी चुनौतियों का सामना करने के योग्य बनाता है, बल्कि उनका (यानि प्रकृति एवं मानव संसाधनों का) भविष्य में न्यायपूर्ण उपयोग करने की राह भी दिखाता है। इस सबसे ऊपर, इस कार्यक्रम को लागू करना नयी उभर रही प्रकृति-मानव केंद्रित व्यवस्था में तर्कसंगत मानव एवं एक विवेकपूर्ण और संवेदनशील मानव समाज के क्रमिक विकास के लिए अत्यधिक समुचित हालात पैदा करेगा।

प्रकृति-मानव केंद्रित व्यवस्था पर्यावरण हितों के साथ-साथ मानवीय मसलों को जोड़ने वाली एक विश्व व्यवस्था होगी, एवं विश्व जो मानवीय व्यवस्था के अनुकूल होगा, न कि मानवीय लालच अभिमुख; एक विश्व जो युद्ध-विहीन और सीमा-विहीन होगा; एक विश्व जो टिकाऊ, समता, उत्पादकता, लोकतंत्र एवं पारदर्शिता के विकास मॉडल पर आधारित होगा, जो आय में केवल 1:5 के अंतर को स्वीकृति देगा तथा सभी वंचित, गरीब, बेरोजगार आदि के लिए सामाजिक सुरक्षा एक मूल अधिकार के रुप में सुनिश्चित करेगा तथा एक विश्व जो पर्यावरणीय एवं मानवीय मूल्यों द्वारा पहचाना जाएगा।

व्यवस्थागत परिवर्तन का समय आ चुका है। आइये, इस अवसर को हम हाथ से जाने न दें।

सज्जन कुमार,
सदस्य,
प्रकृति-मानव केंद्रित जन आंदोलन